



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### रुड़की

खण्ड-13] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 फरवरी, 2012 ई0 (माघ 15, 1933 शक सम्वत्) [संख्या-05

#### विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	155—160	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	9—12	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## औद्योगिक विकास अनुभाग-2

## कार्यालय ज्ञाप

18 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2930/VII-II/123-उद्योग/08/2011-उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिये जाने व औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किए जाने हेतु अधिसूचना संख्या 488/औ0 वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 28 फरवरी, 2008 के द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किए जाने हेतु प्रोत्साहन सुविधाओं को बढ़ाने, रियायतों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि आदि के द्वारा वर्तमान नीति को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के लिए श्री राज्यपाल दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 में निम्नानुसार संशोधन एवं परिवर्द्धन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

## विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (यथासंशोधित/परिवर्द्धित), 2011

2-विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 में निम्नानुसार स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्राविधानों को रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-1

## वर्तमान प्राविधान

प्रस्तर-2 दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण : श्रेणी-बी

जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू-भाग तथा देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर व जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकास खण्ड को छोड़कर इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान

प्रस्तर-2 दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण : श्रेणी-बी

जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू-भाग तथा देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर व जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकास खण्ड को छोड़कर इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर विकास खण्ड तथा देहरादून जनपद के रायपुर व सहसपुर विकास खण्ड के 650 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले स्थानों (सेलाकुई/लांघा रोड, पटेलनगर/मोहब्बेवाला/लाल तप्पड़, कुँआवाला आदि औद्योगिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं होंगे) में विनिर्माणक (manufacturing) पात्र औद्योगिक इकाईयों को भी नीति के अन्तर्गत प्रदत्त विशेष राज्य पूंजी उपादान तथा विशेष ब्याज प्रोत्साहन सहायता का लाभ ही श्रेणी-बी में वर्गीकृत क्षेत्रों में अनुमन्य सीमा/मात्रा में उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में निजी सहभागिता से औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने पर नीति में प्रदत्त भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अवस्थापना विकास सुविधाओं में किये गये व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि, अधिकतम रु0 50 लाख अनुदान स्वरूप अनुमन्य होगी।

प्रस्तर-3 योजना की वैधता अवधि : यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, लागू रहेगी।

प्रस्तर-4 योजना से व्यवहृत इकाईयां एवं पात्रता क्षेत्र :

योजना लागू होने के पश्चात् स्थापित ऐसे अभिज्ञात नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों, जिन्होंने अपने उद्यम की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की हो तथा उद्यम की स्थापना के लिए संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो, को पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं/रियायतों का लाभ प्राप्त होगा। स्थापित उद्यम के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर ये सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी।

प्रस्तर-5 विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य छूट :

(1) भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना :

(iv) उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनाई जायेगी।

प्रस्तर-(10) विपणन प्रोत्साहन सहायता :

3-राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थापित विनिर्माणक/उत्पादक औद्योगिक इकाईयों को राजकीय क्रय में मूल्य वरीयता में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता प्रदान की जायेगी।

प्रस्तर-3 योजना की वैधता अवधि : यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, लागू रहेगी। पात्र इकाईयों, जो 31 मार्च, 2015 तक स्थापित होंगी को स्थापित होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिये योजना में प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। इसके पश्चात् मार्च 2018 तक स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से क्रमशः 9, 8 तथा 7 वर्ष के लिए अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध होंगी।

प्रस्तर-4 योजना से व्यवहृत इकाईयां एवं पात्रता क्षेत्र :

योजना लागू होने के पश्चात् स्थापित ऐसे अभिज्ञात नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों, जिन्होंने अपने उद्यम की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की हो तथा उद्यम की स्थापना के लिए संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो, को पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं/रियायतों का लाभ प्राप्त होगा।

नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं के लिये अधिसूचित स्थलों/वर्गीकृत जनपदों में दिनांक 1-4-2008 से पूर्व स्थापित ऐसी मैन्यूफैक्चरिंग औद्योगिक इकाईयां, जो संशोधित अधिसूचना जारी होने की तिथि के पश्चात् अपने वर्तमान अचल पूंजी निवेश में 25 प्रतिशत से अधिक की अभिवृद्धि करते हो तथा इससे उनकी उत्पादन क्षमता में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हो, तो ऐसी सभी उत्पादक इकाईयों को भी नीति/योजना में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

प्रस्तर-5 विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य छूट :

(1) भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना :

(iv) उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनाई जायेगी।

मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों में भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी।

प्रस्तर-(10) विपणन प्रोत्साहन सहायता :

3-पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाईयों को, जो ए अथवा बी श्रेणी में हों, को 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत क्रय/मूल्य वरीयता राजकीय क्रय में प्रदान की जायेगी।

प्रस्तर—(11) वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की मात्रा :

1—सभी पूंजी उपादान योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि सभी प्रकार के पूंजी व विशेष पूंजी उपादानों से मिलने वाले कुल अनुदान की धनराशि इकाई में लगे अचल पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत (अधिकतम रु0 60 लाख) से अधिक नहीं होगी।

प्रस्तर—(11) वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की मात्रा :

1—सभी पूंजी उपादान योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता से मिलने वाली कुल अनुदान की धनराशि कुल अचल पूंजी विनियोजन का 60 प्रतिशत, अधिकतम रु0 60 लाख से अधिक न हो। निर्धारित अधिकतम रु0 60 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति सहायता से सम्बन्धित वित्तीय प्रोत्साहन यथा मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति, प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता, ब्याज प्रोत्साहन सहायता, विशेष राज्य परिवहन उपादान की सुविधा आदि सम्मिलित नहीं होंगे। यदि किसी इकाई ने राज्य सरकार से पूंजी उपादान के रूप में अनुदान प्राप्त किया है तो इकाई को राज्य सरकार के एक ही श्रोत से राज्य पूंजी उपादान की सुविधा अनुमन्य होगी।

14—अतिरिक्त/नवीन प्राविधान :

(1) नीति के प्रस्तर—1 में चिन्हित उद्यम—7, “पंचगव्य द्रव्य” उद्योग।

(2) पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड आवंटन का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को होगा।

(3) पर्वतीय क्षेत्रों में 11 इण्डस्ट्रीयल हब (औद्योगिक क्षेत्र) सिडकुल के माध्यम से विकसित किये जायेंगे, जो आधुनिक मूलभूत सुविधाओं से युक्त होंगे एवं इनमें भूमि उपयुक्त दरों पर उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला प्रशासन के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर सिडकुल द्वारा लैण्ड बैंक बनाया जायेगा। उद्योग विभाग द्वारा स्थापित मिनी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में अवस्थापना एवं सामान्य सुविधाओं को सिडकुल/सीडा द्वारा विकसित किया जायेगा।

(4) सभी जिला उद्योग केन्द्रों में “उद्यम प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की सुगमता केन्द्र” (Enterprises Promotion and Single Window Facilitation Centre) स्थापित किये जायेंगे। इनमें औद्योगिक विकास के अन्तर्गत सम्मिलित सभी विभागों/संस्थाओं (सिडकुल, खनन, खादी) के अधिकारी तैनात होंगे तथा इन केन्द्रों पर राज्य सरकार की सभी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी। ये केन्द्र उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस केन्द्रों को वीडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से उद्योग निदेशालय एवं सिडकुल के मुख्यालय से जोड़ा जायेगा तथा उद्यमियों से सीधे वार्तायें आयोजित की जायेंगी। समय-समय पर विशेषज्ञों, बैंक अधिकारियों एवं विशिष्ट संस्थाओं के उच्च अधिकारियों से भी सीधी वार्तायें आयोजित की जायेंगी।

18 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2931/VII-II/123-उद्योग/08/2011-औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-488/सात-II-08/08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति में घोषित अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के लिए अधिसूचना संख्या 1961/VII-II/123-उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा गठित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली-2008 में निम्नवत् संशोधन किए जानी की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2—विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली-2008 के प्रस्तर-9 अचल पूंजी निवेश के प्राविधान के अन्तर्गत वर्तमान प्राविधान-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्राविधान रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

## स्तम्भ-1

## स्तम्भ-2

## वर्तमान प्राविधान

2. भवन-इकाई की कार्यशाला हेतु आवश्यक भवन के क्रय अथवा उसके निर्माण पर किये गये वास्तविक व्यय को भवन का मूल्य माना जायेगा। आवासीय तथा कार्यालय भवनों को भवन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किराये के निजी भवन में स्थापित मशीनों, संयंत्रों व उपकरणों पर विनियोजित धनराशि पर उपादान की पात्रता के लिये न्यूनतम 15 वर्ष का पंजीकृत किरायानामा आवश्यक होगा। सरकारी संस्था से लिये गये भवन के मामले में किराये की कोई न्यूनतम अवधि न होगी।

## एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान

2. भवन-इकाई की कार्यशाला हेतु आवश्यक भवन के क्रय अथवा उसके निर्माण पर किये गये वास्तविक व्यय को भवन का मूल्य माना जायेगा। आवासीय तथा कार्यालय भवनों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किराये के निजी भवन में स्थापित मशीनों, संयंत्रों व उपकरणों पर विनियोजित धनराशि पर उपादान की पात्रता के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में किराये के भवनों में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिये भवन किराये की न्यूनतम अवधि 7 वर्ष तथा भूमि को लीज पर लिये जाने की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित होगी। इकाई को कम से कम 03 वर्ष तक उत्पादनरत रहना आवश्यक होगा। सरकारी संस्था से लिये गये भवन के मामले में किराये की कोई न्यूनतम अवधि न होगी।

18 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2932/VII-II/123-उद्योग/08/2011-औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-488/सात-II-08/08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति के लिए प्रस्तर-5 में इंगित प्रोत्साहन, सुविधाओं हेतु अधिसूचना संख्या : 2373/VII-II/123-उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (वैट) से छूट हेतु क्रमांक-1 पर गठित "विनिर्माणक क्षेत्र के नये उद्यमों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति नियमावली, 2008" में कतिपय निम्नवत् संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विनिर्माणक क्षेत्र के नये उद्यमों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति नियमावली-2008 के नियम-5 एवं 6 में निम्नानुसार स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्राविधानों को रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

## स्तम्भ-1

## स्तम्भ-2

## वर्तमान प्राविधान

## एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान

## 5. स्वीकार्य मूल्य वर्धित कर (VAT):

पात्र औद्योगिक एककों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर स्वीकृत सहायता की सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा श्रेणी-ए के जनपदों के लिए कुल कर देयता का 90 प्रतिशत तथा श्रेणी-बी के जनपदों में कुल कर देयता का 75 प्रतिशत होगी। उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थायी निवासियों द्वारा श्रेणी-बी के जनपदों में स्थापित उद्यमों को भी मूल्य वर्धित कर में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता श्रेणी-ए के जनपद के समान अर्थात् 90 प्रतिशत देय होगी।

## 5. स्वीकार्य मूल्य वर्धित कर (VAT):

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों के निर्माण के सम्बन्ध में जो वैट सम्बन्धी इनपुट (प्रान्तीय खरीद पर देय) एवं आउटपुट टैक्स की देयता होगी, पात्रता के आधार पर अनुमन्यता के अनुसार इसका भुगतान वाणिज्य कर विभाग को संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के सत्यापन के आधार पर उद्योग विभाग अथवा उद्योग विभाग द्वारा नामित संस्था द्वारा उद्यमी की ओर से कर दिया जायेगा जिससे कि वैट चैन भी अक्षुण्ण बनी रहे और उद्यमी को इनपुट (प्रान्तीय खरीद पर देय) एवं आउटपुट टैक्स का पात्रता के अनुसार देय छूट का लाभ भी अनुमन्य हो सके। उक्त के क्रियान्वयन हेतु ऐसी इकाईयों द्वारा अपने बिक्री की विवरणी (रिटर्न) वाणिज्य कर विभाग में तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अगले माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे जिससे कि विवरणी (रिटर्न)

सहित कर निर्धारित तिथि तक वाणिज्य कर विभाग में प्राप्त हो जाय। जिन इकाईयों का उत्पादन होने के एक वर्ष पश्चात् भी इनपुट टैक्स का दावा आउटपुट टैक्स के सापेक्ष अधिक रहता है वह प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगी।

**6. मूल्य वर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया—**

मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिलास्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

**6. मूल्य वर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया :-**

मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-4 की उपधारा (6) में टैक्स रिबेट सम्बन्धी अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा उद्योग विभाग के परामर्श पर निर्गत की जायेगी।

इस प्रकार की छूट प्राप्त करने वाली इकाईयों की वार्षिक समीक्षा वाणिज्य कर व उद्योग विभाग के नामित अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

इस प्रकार की इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपनी खरीद जिस पर कि उसे लाभ लेना है, उसे प्रान्त के अन्दर के पंजीकृत टिन (TIN) धारक करदाता से करेगा। इसका उल्लेख खरीद बिलों में करेगा।

उद्योग विभाग द्वारा छूट की पात्रता वाली इकाईयों की ओर से वाणिज्य कर विभाग को देय रिबेट के समतुल्य धनराशि जमा करायी जायेगी और इसको जमा करने की प्रक्रिया का निर्धारण वाणिज्य कर विभाग/वित्त विभाग व उद्योग विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया जायेगा। प्रान्त के अन्दर की खरीद पर इकाई द्वारा दिये गये इनपुट टैक्स की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा वैट के अन्तिम कर निर्धारण के उपरान्त की जायेगी।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,  
प्रमुख सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 फरवरी, 2012 ई0 (माघ 15, 1933 शक सम्वत्)

### भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 21, 2011

**No. 277/UHC/Admin. A/2011**--In exercise of the powers conferred by Rule 27 (ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, the Hon'ble Court is pleased to grant the Supertime Scale of ₹ 70,290-1,540-76,450 to the following officers after completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre from the date mentioned against their names :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of grant of Supertime Scale
1.	Sri Kawer Sain	01.07.2011
2.	Ms. Kumkum Rani	13.09.2011

By Order of the Court,  
Sd/-  
RAM SINGH,  
Registrar General.

December 22, 2011

**No. 278/XIV/63/Admin.A/2003**--Ms. Neetu Joshi, the then Civil Judge (Sr. Div.), Champawat, presently posted as Addl. District Judge, Vikasnagar, Distt. Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 17.10.2011 to 19.10.2011.

December 22, 2011

**No. 279/XIV/74/Admin.A/2003**--Sri Bharat Bhushan Pandey, the then Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, presently posted as Addl. District & Sessions Judge/F.T.C., Pauri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 24.11.2011 to 09.12.2011 with permission to suffix 10.12.2011 and 11.12.2011 as 2<sup>nd</sup> Saturday and Sunday holidays.



December 22, 2011

**No. 280/XIV-90/Admin.A/2003**--Sri Mithilesh Jha, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, is hereby sanctioned medical leave for 03 days *w.e.f.* 07.12.2011 to 09.12.2011.

December 22, 2011

**No. 281/XIV-a-1/Admin.A/2009**--Sri Rakesh Kumar Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 24 days *w.e.f.* 29.10.2011 to 21.11.2011 with permission to prefix 25.10.2011 to 27.10.2011 as Deepawali holidays and 28.10.2011 as local holiday.

December 22, 2011

**No. 282/XIV-67/Admin.A/2003**--Sri Rakesh Kumar Mishra, 4<sup>th</sup> Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 21.11.2011 to 09.12.2011 with permission to prefix 20.11.2011 as Sunday and to suffix 10.12.2011 and 11.12.2011 as 2<sup>nd</sup> Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

**PRASHANT JOSHI,**  
*Registrar (Inspection).*

#### NOTIFICATION

December 23, 2011

**No. 283/UHC/Admin.A/2011**--Ms. Monika Mittal, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is given additional charge of Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, in addition to her duties.

December 23, 2011

**No. 284/UHC/Admin.A/2011**--Sri Sujeet Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Nainital is given additional charge of Civil Judge (Jr. Div.), Nainital in addition to his duties.

December 23, 2011

**No. 285/UHC/Admin.A/2011**--Sri Ashutosh Kumar Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

December 23, 2011

**No. 286/UHC/Admin.A/2011**--Sri Yogendra Kumar Sagar, 3<sup>rd</sup> Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as Special Judicial Magistrate (C.B.I.), Dehradun, *vice* Ms. Anuradha Garg.

December 23, 2011

**No. 287/UHC/Admin.A/2011**--Sri Vinod Kumar Burman, 2<sup>nd</sup> Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, Distt. Almora, *vice* Sri Vivek Dwivedi.

December 23, 2011

**No. 288/UHC/Admin.A/2011**--Smt. Jyoti Bala, 4<sup>th</sup> Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 1<sup>st</sup> Judicial Magistrate, Dehradun, *vice* Sri Shiva Kant Dwivedi.

December 23, 2011

**No. 289/UHC/Admin.A/2011**--Sri Rajeev Dhavan 3<sup>rd</sup> Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, *vice* Ms. Meena Deopa.

December 23, 2011

**No. 290/UHC/Admin.A/2011**--Sri Mohd. Yakub, 2<sup>nd</sup> Add. Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, Distt Nainital is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur, Distt. Champawat, *vice* Smt. Geeta Chauhan.



December 23, 2011

**No. 291/UHC/Admin.A/2011**--Sri Mithilesh Jha, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is promoted, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Almora in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, in the vacant Court.

December 23, 2011

**No. 292/UHC/Admin.A/2011**--Sri Dharmendra Singh Adhikari, Joint Secretary (Law), Government of Uttarakhand, Dehradun is promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.), in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010.

December 23, 2011

**No. 293/UHC/Admin.A/2011**--Ms. Anuradha Garg, Special Judicial Magistrate (C.B.I.), Dehradun is promoted and posted as 1<sup>st</sup> Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, in the vacant Court.

December 23, 2011

**No. 294/UHC/Admin.A/2011**--Sri Shiva Kant Dwivedi, 1<sup>st</sup> Judicial Magistrate, Dehradun is promoted and posted as 2<sup>nd</sup> Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, in the vacant Court.

December 23, 2011

**No. 295/UHC/Admin.A/2011**--Sri Vivek Dwivedi, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, Distt. Almora is promoted, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, vice Sri Ashutosh Kumar Mishra.

December 23, 2011

**No. 296/UHC/Admin.A/2011**--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur, Distt. Champawat is promoted, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Champawat in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, in the vacant Court.

December 23, 2011

**No. 297/UHC/Admin.A/2011**--Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar is promoted and posted as Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, in the vacant Court.

December 23, 2011

**No. 298/UHC/Admin.A/2011**--Ms. Ranji Shukla, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is promoted, transferred and posted as Asstt. Sessions Judge [Civil Judge (Sr. Div.)]/F.T.C., Haldwani, Distt. Nainital in the pay scale of ₹ 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, in the vacant Court.

By Order of the Court,

Sd/-  
RAM SINGH,  
Registrar General.

December 23, 2011

**No. 299/UHC/Admin.A/2011**--Pursuant to the Government Notification No. 237/XXXVI(1)/2011-09-Bha.Sa/2001, dated 22.12.2011, issued in exercise of powers vested U/S 36A of N.D.P.S. Act, 1985, Sri Subir Kumar, Addl. District & Sessions Judge/1<sup>st</sup> F.T.C., Roorkee, Distt. Hardwar is conferred powers to preside over the Special Court at Roorkee, Distt. Hardwar, constituted under N.D.P.S. Act, 1985, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

**RAM SINGH,**

*Registrar General..*